



पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब न हो, इसके लिये कार्यालय प्रमुख को वेतन निर्धारण कोषालय होगा परन्तु उसकी जांच संबंधित कोषालय अधिकारी तथा संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं वेतन विभाग को सौंपा जाएगा । परन्तु वेतन को निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा किये गये वेतन निर्धारण तथा उनकी प्रमाणित जानकारी के आधार पर पेंशन प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

1/ जांच से गलत जानकारी/गलत वेतन निर्धारण के कारण यदि राशि वसूली की आवश्यकता हुई तो एनो नमूली पेंशन प्रकरण के निराकरण को नाद प्राप्त होने वाली पेंशन तथा अन्य देय राशियों में से की जा सकेगी । इन हेतु पेंशन प्रकरण कोषालय/संचालक, पेंशन कार्यालय को भेजने से पूर्व आवश्यक रूप से जांच की जायेंगी । प्रक्रिया में लिये जाये जायेंगी एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु तथा शेष 2 प्रति पेंशन कोषालय कार्यालय को भेजी जायेगी । पेंशन कोषालय जांच प्रतिपूर्ति बंध की एक प्रति कोषालय को साथ संलग्न कर जिला स्थान से पेंशन प्रकरण प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ के कोषालय पर भेजी जावेगी । प्रतिपूर्ति बंध के आधार पर अधिक भुगतान (विन्नी चरणों से) होने की दशा में महंगाई वादा, ग्रेच्युटी, वायुटेशन व पेंशन की राशि तथा अन्य देय राशियों से अधिक भुगतान की राशि वसूली जायेगी । प्रतिपूर्ति बंध इन निर्देशों के साथ प्रपत्र-2 में संलग्न है ।

2/ पेंशन को वर्तमान में प्रचलित 30 प्रपत्रों के स्थान पर पेंशन के सखीकृत चार प्रपत्र निम्नलिखित किये जाये हैं जो इन निर्देशों के साथ संलग्न हैं इन प्रपत्रों को क्रमशः पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/सारांशिकरण की स्वीकृत हेतु प्रपत्र नाम दिये गये हैं । 01 अक्टूबर 02 से पेंशन प्रकरण कोषालय इन्हीं प्रपत्रों में भेजा जायेगा । उक्त तिथि के पूर्व इन नये प्रपत्रों के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित प्रपत्रों में पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालयों द्वारा तबतक किये जायेंगे ।

3/ इन्टीकेट सेवापुस्तिका एवं जन्मतिथि की जांच और ओवर सर्टिफिकेट की दशा में जन्मतिथि की जांच के अधिकार जिला स्तर के पेंशन प्रकरणों को लिए सखीकृत व विभागाध्यक्ष कार्यालयों को लिए संचालक पेंशन/संयुक्त संचालक कोषालय को भेजा जायेगा । सखीकृत प्रकरणों की जांच कोषालय को भेजा जायेगा ।

4/ संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालयों का निरीक्षण जाड़िट कर सकेंगे । इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं ।

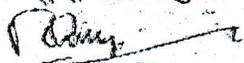
5/ कोषालय अधिकारी द्वारा निरकृत पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के लिये जिला स्तर पर पेंशन समिति का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष-कलेक्टर, सचिव-कोषालय अधिकारी एवं सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे । समिति द्वारा पेंशन प्रकरणों की समीक्षा पर प्रतिवेदन आशयक्त कोष एवं लेखा तथा संचालक, पेंशन को भेजा जायेगा । पेंशन समिति द्वारा संचालक कार्यालय प्रमुख को बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ बुलाया जा सकेगा ।

6/ कोषालय द्वारा निराकरण किये गये प्रकरण एवं जिला स्थित कार्यालयों में ललित प्रकरणों की निश्चित समीक्षा जिला योजना समिति की लोक लेखा समिति द्वारा की जावेगी ।

(3)

विभाग चार पर निम्नवृत्त एवं जिला कार्यालयों में लॉक प्रकरणों की जानकारी प्रतिमाह विभागवार  
जिला कार्यालय की कार्यवाही प्रतिमाह गैरानुसूचित जातों को प्रेषित करेंगे। इस संबंध में जिला कोषालयों को प्रपत्र  
प्रमाण, गैरानुसूचित जातों के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर भेजा दिये जायेंगे।  
प्रमाण चार पर समीक्षा करने के लिये संचालक, गैरानुसूचित जात प्रतिमाह विभागवार, जिलेवार तथा  
प्रमाण जानकारी वित्त विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।  
इस प्रक्रिया में अनुरोध किये गये प्रावधानों के अनुसार 20प्र0 सिविल सर्विलेज (पेंशन) नियम 1976  
के अन्तर्गत सिविल सेवा पेंशन वन सम्बन्धीन नियम 1976 के नियमों एवं उनके संलग्न प्रपत्रों को  
अनुसूचित जातों तथा सीमा तक सम्बन्धित माना जाये। उक्त नियमों में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये  
जायेंगे।

लक्ष्य: - सरलीकृत चार पेंशन प्रपत्र।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
संज्ञा आदेशानुसार  
  
उप सचिव  
20प्र0 शासन, वित्त विभाग

130  
131

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

कमांकसी/3-3/1/3/08

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2008

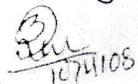
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  
मध्य प्रदेश ।

विषय :- वेतनमान रूपये 6500-10500 में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों  
को राजपत्रित घोषित करने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधी भरती और पदोन्नति  
से भरे जाने वाले वेतनमान 6500-10500 के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दो  
घोषित किया जाये

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग